उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

रिट याचिका (एम/एस) संख्या 2825/2021

शेखर सिंह पापोला ... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... प्रतिवादी

अधिवक्तागण :

श्री डी. के. जोशी, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

श्री प्रदीप हैरिया, उत्तराखंड राज्य के स्थायी अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा

09 जून, 2016 को याचिकाकर्ता ने वादी संख्या 1 के रूप में एक वाद वाद संख्या 33/2016, शेखर सिंह पपोला और अन्य बनाम ठाकुर सिंह और अन्य, उन संपत्तियों के संबंध में, जिनका वर्णन राहत खंड में किया गया था, जो यहां नीचे उद्धृत किया गया है, संस्थित किया था,

अतः प्रार्थना है कि डिक्री वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण सं ० 1 के विरुद्ध निम्न आशय की पारित की जाय ।

(अ)-कि प्रतिवादी सं ० 1 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाय कि वह ग्राम गुलमपरगड़, तहसील कपकोट, जिला बागेश्वर के खतौनी खाता सं ० 23 के पै ० खेत न ० 7838, 7839 7840, 7864, 7865, 7866 की भूमि में किसी किस्म का हस्तक्षेप करने से हमेशा के लिए निषिद्ध रहे ।

(ब) – कि प्रतिवादी सं ० 1 के विरुद्ध आदेशात्मक व्यादेश जारी किया जाय कि वह पैरा 1 में वर्णित भूमि को साबिक सूरत में रखे ।

(स)-कि प्रतिवादी सं0 1 विवादित भूमि में साबिक सूरत रखने के बाद रिक्त कब्जा वादीगण को प्रदान करें ।

(द)-कि खर्चा मुकदमा जिम्मे प्रतिवादी नं ० 1 हो तथा न्यायालय वादी के पक्ष में जो उचित समझे वह डिक्री भी वादीगण को दिलायी जाय ।"

2. उक्त वाद अपने गुण-दोष पर आगे बढ़ा, और यह 2019 के मूल वाद संख्या 13, शेखर सिंह पपोला बनाम ठाकुर सिंह व अन्य दिनांकित 29 फरवरी 2020, सिविल जज (सीनियर डिवीजन), बागेश्वर के विद्वान न्यायालय द्वारा अपने निर्णय और डिक्री &,द्वारा तय किया गया था। जिसे बाद में 15 फरवरी 2021 को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत द्वारा सिविल अपील संख्या 2 सन 2020 मे दिए गए फैसले और डिक्री द्वारा पुष्टि की गई थी।

इस प्रकार याचिकाकर्ता द्वारा दायर मुकदमे में राज्य और लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को क्रमशः प्रतिवादी संख्या २ और ३ के रूप में पक्षकार बनाया गया था। इसका मतलब यह है कि प्रतिवादियों के पक्ष में इस प्रकार समवर्ती रूप से तय किया गया वाद, वाद के पक्षकारों पर समान रूप से बाध्यकारी प्रभाव डालेगा, हालांकि, समवर्ती निर्णय जो संपत्ति के एक ही सेट के संबंध में, संबंधित विद्वान सिविल कोर्ट द्वारा दिए गए थे. अब एक दूसरी अपील में विचार का विषय था, दूसरी अपील संख्या 70 वर्ष 2021, शेखर सिंह पपोला और अन्य बनाम ठाकुर सिंह और अन्य, जो यहां अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता द्वारा उसी वकील के माध्यम से 27 जुलाई 2021 को शुरू किया गया था।

3. एक और द्वितीय अपील हुई थी, दूसरी अपील संख्या 71/2021, शेखर सिंह पपोला और अन्य बनाम ठाकुर सिंह और अन्य, जिसे यहां अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता द्वाराअधिमानित किया गया था, जिसने वाद संख्या 13/2019, शेखर सिंह पपोला बनाम ठाकुर सिंह और अन्य में मुद्दा संख्या 3 को तय करने के रूप में निचली अदालतों द्वारा पारित निर्णय को चुनौती दी थी।मुद्दा संख्या 3 पर जो निर्णय लिया गया था, वह इस बारे में था कि क्या वाद प्रांग न्याय res judicata के सिद्धांत द्वारा वर्जित होगा? यह निर्णय सी. पी. सी. की धारा ११ के तहत निहित प्रावधानों के आलोक में लिया गया था, जिसकी बाद में सिविल अपील संख्या २/2020, शेखर सिंह पपोला बनाम ठाकुर सिंह और अन्य में पुष्टि की गई थी, और इस प्रकार सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा तय की गई इन कार्यवाहियों में, अपीलार्थी/याचिकाकर्ता के खिलाफ एक समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किया गया है। इस फैसले के खिलाफ भी, एक और दूसरी अपील, दूसरी अपील संख्या 71/2021, शेखर सिंह पपोला और अन्य बनाम ठाकुर सिंह और अन्य, विचाराधीन है, जिसे उसी वकील द्वारा 27 जुलाई, 2021 को इस न्यायालय की रजिस्ट्री के समक्ष दाखिल की गई थी।

4. इतना ही नहीं, बल्कि याचिकाकर्ता ने पहले रिट याचिका, रिट याचिका (एम/एस) संख्या 214/2013, शेखर सिंह पपोला बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य के रूप में दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जो प्रत्यर्थियों द्वारा पारित आदेश के खिलाफ व्यथित था, जिसका निस्तारण इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने जिलाधिकारी को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के निर्देश के साथ किया।

5. पहले की रिट याचिका में, वाद कारण, जो याचिकाकर्ता द्वारा प्रलोभित किया गया था, प्रत्यर्थी नं. 8 द्वारा अतिक्रमण के कथित कार्य के संबंध में था, जो खाता संख्या 23 में पड़ी श्रेणी 5 भूमि, वर्तमान रिट याचिका के पैरा 27 में वर्णित, के खिलाफ मुकदमे में प्रतिवादी नंबर 1 था।

6. उसी वकील के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने 5 दिसंबर 2021 को इस रिट याचिका को दाखिल किया था, बेशक दूसरी अपील दायर करने के तथ्य को जानने के बाद और उसके विचाराधीनता के दौरान, रिट याचिका में राहत को निम्नलिखित तरीके से संशोधित कियाः

'प्रार्थना

इसलिए, सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपा करे -

(I) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें कि निजी प्रतिवादी संख्या 7 और 8 को बागेश्वर जिले की कपकोट तहसील के ग्राम गुलाम पारगढ़ और नारगड़ा के क्षेत्र में अवैध रूप से निर्मित सड़क पर खनिजों के परिवहन से रोका जाए।

(II) उपरोक्त भूमि पर अवैध गतिविधियों के कारण सार्वजनिक भूमि को हुए नुकसान के लिए उत्तरदाताओं संख्या 7 और 8 के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

(iii) निजी प्राप्तकर्ताओं के पक्ष में जारी 16 अगस्त, 2017 के सरकारी आदेश और निजी पते के पक्ष में 19.08.2000 के सरकारी आदेश की समीक्षा करने/वापस लेने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसके तहत खानों और खनिजों की खुदाई और उत्खनन के लिए पट्टा दिया गया है।

(IV) इस मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने और जिम्मेदार अधिकारियों सहित दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए उत्तरदाताओं को परमादेश देने की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

(v) एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसे माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और उचित समझे।लागत अधिनिर्णीत करें।"

7. वास्तव में, राहत का मॉड्यूलेशन, यदि इसे रिट याचिका के अभिवचनों के आलोक में ध्यान में रखा जाता है, यह उस संपत्ति के संबंध में था, जो विषय वस्तु थी, जिसके लिए राहत की मांग की गई थी, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं रिट याचिका में वर्णित किया गया है, जो कि वही संपत्ति होती है, जो मुक़दमे की विषय वस्तु थी, जिसके खिलाफ द्वितीय अपील विचाराधीन है। वास्तव में, 5 दिसंबर 2021 को बाद की रिट याचिका का सहारा लेना कुछ नहीं था, बल्कि एक समझदार उपकरण था, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा फैसले और डिक्री के प्रभाव की अवहेलना करने के लिए अपनाया गया था, जिसे सक्षम नियमित सिविल न्यायालयों द्वारा समवर्ती रूप से तय किया गया था, जो उन्ही भूमि के संबंध में, जिसका उल्लेख वादपत्र में किया गया था और जिसका वर्णन पैरा 27 में वर्तमान रिट याचिका में किया गया है। इतना ही नहीं, यह रिट याचिका सीपीसी के आदेश 2, नियम 2, सपठित धारा 11 के तहत निहित प्रावधानों द्वारा वर्जित होगी, जब उसकी पहली रिट याचिका संख्या 214/2013, पहले से ही 8 मार्च 2013 को तय की गई थी, और उसके बाद याचिकाकर्ता द्वारा, 9 जून 2016 को सिविल कोर्ट के समक्ष मुकदमा दायर किया गया था, यानी पहले की रिट याचिका संख्या 214/२०१३ के फैसले के बाद, जो 8 मार्च 2013 को इस अदालत की समन्वय पीठ द्वारा तय किया गया था।

8. वास्तव में, यह एक उपयुक्त मामला है, जहां पत्रावली से ही पता चलता है कि यह कानून की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा फैसले और डिक्री के प्रभाव की अवहेलना करने के लिए जानबूझकर और समवर्ती रूप से अपनाया गया है, जो सक्षम सिविल कोर्ट द्वारा समवर्ती रूप से दिया गया है, जो अभी भी दूसरी अपील का विषय है, जिसे 27 जुलाई 2021 को उसी अधिवक्ता के माध्यम से यहां अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता ने स्थापित किया था, जो वर्तमान रिट याचिका में अधिवक्ता है।

9. अंतर, जिसे याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तराशने का प्रयास किया गया है, वह यह है कि वास्तव में, रिट याचिका पर, इस तथ्य के कारण कि रिट याचिका विचाराधीन है, रोक नहीं लगाई जाएगी क्योंकि यहां, वर्तमान रिट याचिका में, यह राज्य एजेंसियों की ओर से एक निष्क्रियता है, जिसे रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के रूप में शामिल किया गया है, जिन्हे उस गतिविधि पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके लिए भूमि के उसी टुकड़े से संबंधित रिट याचिका में राहत मांगी गई है, जो वकील द्वारा विवादित नहीं है.

10. वास्तव में, याची का यह अभिवाक कि रिट याचिका वर्जित नहीं होगी, क्योंकि यह राज्य की निष्क्रियता है, जो वर्तमान रिट याचिका में चुनौती की विषय वस्तु है, इस न्यायालय द्वारा स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वाद, जिसे याची द्वारा दाखिल किया गया, वास्तव में, राज्य एजेंसी को वाद में प्रतिवादी के रूप में अभ्यारोपित किया गया था और उस स्थिति में, प्रतिवादी और राज्य के बीच उसी संपत्ति के संबंध में परस्पर अधिकार, उस कार्यवाही के आदेश पर, जो स्वयं याची द्वारा संस्थित की गई थी, सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा विनिश्चित की गई थी, जिसने स्वयं वाद में राज्य को प्रतिवादी होने का विकल्प चुना था और एक बार उसने 2013 में प्रस्तुत की गई पहले की रिट याचिका के फैसले मे प्रस्तुत किया था, और बाद में 2016 में एक वाद प्रस्तुत किया था, और दोनों न्यायालयों से समवर्ती रूप से हार गया था और उसके बाद 27 जुलाई 2021 को इस न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपीलें दायर की थी, जो अभी भी विचाराधीन है, यह बिना कहे स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता इस तथ्य के प्रति सचेत था कि उसने पहले से ही दूसरी अपील में और साथ ही साथ, पहले की रिट याचिका में संपत्तियों के उसी समूह के संबंध में एक वाद कारण को उठाया और एक चतुर अंतर जिसे निकालने की कोशिश की गई है, कि रिट याचिका में, यह राज्य एजेंसियों के कार्य को शामिल करता है, जो एक विषय वस्तु रहा है, वास्तव में, याचिकाकर्ता की ओर से उसके खिलाफ समवर्ती रूप से प्रस्तुत सिविल डिक्री के प्रभाव और परिणामों से न्यायालय का ध्यान विचलित और भटकाने के अलावा कुछ भी नहीं है, और जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, याचिकाकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता के संभावित से अंतर करने के तर्क की यह सूक्ष्मता, कि रिट याचिका राज्य एजेंसी की ओर से एक निष्क्रियता पर विचार करती है, वह अवधारणा है जो इस न्यायालय द्वारा स्वीकार्य नहीं है, जबकि याचिकाकर्ता ने स्वयं वाद में वादी के रूप में राज्य और लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को प्रतिवादी के रूप में चुना है और उसमें भी, यह वही संपत्ति विषय वस्तु थी, इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि वर्तमान रिट याचिका एक चतुर और जानबूझकर साधन है जिसे याचिकाकर्ता द्वारा सिविल कोर्ट द्वारा निर्धारित संबंधित अधिकारों द्वारा उसके द्वारा सामना किए जा रहे प्रतिबंधों के प्रभाव को दूर करने के लिए अपनाया गया है, जो दूसरी अपील का विषय है, क्योंकि रिट याचिका 5 दिसंबर 2021 को ही प्रस्तुत की गई थी, यानी दूसरी अपील दायर करने के बहुत बाद।

11. अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरी अपील, द्वितीय अपील संख्या 70/2021 और 71/2021, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा सक्षम सिविल कोर्ट की नियमित समवर्ती डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत दी गई थी, जब 27 जुलाई 2021 को इस न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया था, तो इसे दोषपूर्ण होने के रूप में चिह्नित किया गया था, और उसमें अपीलकर्ता को दोष को हटाने के लिए समन्वय पीठ द्वारा समय दिया गया था, जो 23 अगस्त 2021 तक नहीं किया गया था। इसलिए, वास्तव में, दूसरी अपील में कोई अंतरिम संरक्षण संचालित नहीं होता है, जो याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई , इसलिए, 5 दिसंबर 2021 को प्रस्तुत रिट याचिका के लिए, न्यायालय का यह विचार है कि यह याचिकाकर्ता और उसके वकील की ओर से (इस न्यायालय के समक्ष सभी मामलों में आम) भूमि के उसी सेट के संबंध में एक समवर्ती कार्यवाही का सहारा लेने के लिए एक सचेत और जानबूझकर किया गया कार्य है, जो सिविल न्यायालय की डिक्री का हिस्सा है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका न्यायालय की प्रक्रिया के स्पष्ट दुरुपयोग का सबसे अच्छा उदाहरण है।

12. न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग की अवधारणा मुख्य मुद्दों में से एक है, जिस पर वर्तमान न्यायिक परिदृश्य में ध्यान दिया जाना चाहिए, जहां वादी द्वारा उसी विषय वस्तु या एक ही विषय के संबंध में कानून के अन्य प्रावधानों के तहत एक नया मामला स्थापित करने के लिए पूर्व-संस्थित कार्यवाही में अनुकूल आदेश प्राप्त करने में उसकी विफलता पर विचारपूर्वक और जानबूझकर प्रयास किए जा रहे हैं, और यदि पूर्वोक्त प्रक्रिया का सहारा लेना चालाक इरादे के साथ है, जो वर्तमान मामले में परिलक्षित होता है, जहां लगभग सभी मामलों में वही अधिवक्ता है, जिसने संपत्ति के उसी सेट के संबंध में इस न्यायालय के समक्ष और लगभग समान राहत के लिए कार्यवाही दायर की है, यह वही है जिसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, कि वह न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया और जानबूझकर न्यायालय की कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2008 (1) एससीसी 560, उद्यमी एवं खादी ग्रामोद्योग कल्याण संस्था और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में रिपोर्ट किए गए एक निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया है, जहां पैरा 10 और 16 में निम्नलिखित उद्धरण दिए गए हैंः

"" "."10. हालांकि चार रिट आवेदनों में की गई प्रार्थनाएं स्पष्ट रूप से अलग हैं, रिट आवेदनों के माध्यम से जाने के बाद, यह स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक मामले में मुख्य मुद्दा बैंक द्वारा अपीलकर्ताओं को दी गई राशि की वसूली के आसपास केंद्रित है।स्पष्ट रूप से, कार्यवाही के विभिन्न चरणों में पारित आदेश और मूल राशि पर ब्याज की नई गणना के आधार पर नई कार्यवाही भी समय-समय पर प्रश्नगत रही है.जैसा कि इसमें पहले संकेत दिया गया है कि एक जनहित याचिका भी दायर की गई थी जिसमें अपीलकर्ता नं. २ भी एक पक्षकार था.हो सकता है कि उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 की धारा 35-ए की वैधता इसमें उठाए गए मुद्दों में से एक थी, लेकिन वसूली की कार्यवाही भी इसका विषय था।

16. रिट उपचार एक साम्य उपचार है। उच्च न्यायालय से संपर्क करने वाले व्यक्ति को साफ नीयत के साथ आना चाहिए। इसे न केवल किसी तात्विक तथ्य को दबाना चाहिए, बल्कि बार-बार कानूनी कार्यवाही का सहारा भी नहीं लेना चाहिए, जो कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। महाधिवक्ता, बिहार राज्य बनाम M/S मध्य प्रदेश खैर इंडस्ट्रीज और अन्य [(1980) 3 एससीसी 311] में, इस न्यायालय का मत था कि रिट याचिकाओं को बार-बार दायर करना आपराधिक अवमानना के बराबर है।

13. उक्त सिद्धांत माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व 'निर्णय का औचित्य' ratio के आधार पर प्रतिपादित किए गए हैं, विशेष रूप से, जैसा कि महाधिवक्ता, बिहार राज्य बनाम एम. पी. खैर इंडस्ट्रीज के मामले में विचार किया गया है कि साम्य उपचार हेतु यदि किसी व्यक्ति द्वारा पहुँच कि जाती है तो उसे साफ हाथों से पहुंचना होगा।अपने पक्ष में एक आदेश प्राप्त करने के इरादे से तथ्यों को छुपाने या तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने की अनुमति इस देश की न्यायिक प्रणाली में जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

14. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जिन्होंने उपरोक्त टिप्पणियों का सामना किया, जो वर्तमान रिट याचिका के तर्क के दौरान किए गए थे, ने प्रार्थना की है कि उसे पहले के दिनांक 6 मई 2022 के आदेश के अनुपालन में, दी गई परिस्थितियों में, और उन कारणों के लिए, जिन पर पहले से ही चर्चा की जा चुकी है, एक प्रत्युत्तर हलफनामा दायर करने की अनुमति दी जाए।

15. सबसे पहले, उच्च न्यायालय के नियमों के तहत, प्रत्युत्तर दाखिल करना अधिकार के रूप में नहीं है और इसलिए, वर्तमान रिट याचिका में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के अनुरोध को अस्वीकार किया जाता है। दूसरा, वर्तमान रिट

याचिका में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा विस्तारित बहस के दौरान उभरी स्थिति का सामना करने के बाद, और विशेष परिस्थितियों, जहां याचिकाकर्ता पहले से ही दूसरी अपील जो संपत्तियों के उसी सेट के संबंध में है, में उपचार पाने कि कोशिश कर रहा है, का सामना करने के बाद, , उन्होंने प्रार्थना की कि रिट याचिका को वापस लेने के रूप में खारिज करने की अनुमति दे दी जाए। यह न्यायालय कथित प्रार्थना को अस्वीकार करता है, क्योंकि न्यायालय का वादियों द्वारा परीक्षण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, कि जैसे ही याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका दी जाती है और उसने इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद २२६ के तहत कानून के तहत संरक्षित, नागरिक अधिकार या संवैधानिक या कानूनी वैधानिक अधिकार को लागू करने के लिए इस न्यायालय की रजिस्ट्री के समक्ष दायर किया है, संस्थान के बाद, इसे वापस लेने के लिए यह विकल्प नहीं है, जिसे याचिकाकर्ता के विवेक पर खुला छोड़ दिया जाए और वह भी, वर्तमान मामले की परिस्थितियों में, जब याचिकाकर्ता ने पहले से ही ऊपर चर्चा की गई स्थिति का सामना किया है।

16. इसलिए, रिट याचिका को वापस लिए जाने के रूप में खारिज करने के अनुरोध को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अस्वीकार किया जाता हैः

पहला, रिट याचिका और दीवानी मुकदमे में वर्णित संपत्ति समान रहती है.

दूसरा, सिविल सूट में, राज्य एजेंसी पहले से ही एक पक्षकार थी.

तीसरा, याचिकाकर्ता को पहले से ही नियमित सिविल कोर्ट द्वारा निर्णय-ऋणी के रूप में अधिनिर्णित किया जा चुका है

चौथा, याचिकाकर्ता ने पहले ही एक रिट याचिका दायर की थी जोकि मुकदमा जिसे 2013 में निपटा दिया गया था, दायर करने से पहले की थी।

पांचवां, याचिकाकर्ता ने स्वीकार्य रूप से द्वितीय अपील जोकि दोषपूर्ण थी और जिसे अगस्त 2021 तक ठीक नहीं किया गया था, दायर की थी ।

छठा, जब उसने 5 दिसंबर 2021 को यह रिट याचिका दायर की थी, इन सभी तथ्यों को याचिकाकर्ता, साथ ही उसके वकील को, जो सभी मामलों में समान है, क्योंकि वह सभी कार्यवाही में समान है, को सचेत रूप से पता था, तथा जिससे जो इस नेक पेशे में लगे है,एक पेशेवर सच्चे व्यवहार की उम्मीद थी ।

17. इसलिए, यह रिट याचिका 1 लाख रुपये के खर्च के साथ खारिज की जाती है, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन अधिवक्ता कल्याण कोष में जमा की जाएगी ।यदि लागत की राशि एक महीने में जमा नहीं की जाती है, तो बागेश्वर के जिला कलेक्टर इसकी वसूली सुनिश्चित करेंगे।

(शरद कुमार शर्मा, जे.)
18.05.2022

Mahinder/